

15 हजार आदर्श स्कूल बनेंगे, लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी

■ पीपीपी मॉडल की मदद से 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे ■ एससी छात्रों की पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप को 35,219 करोड़

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

छात्रों के लिए बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। हालांकि नई शिक्षा नीति की जरूरतों के अनुसार देशभर में 15 हजार स्कूलों को सुदृढ़ बनाने की घोषणा की गई। 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। ये स्कूल निजी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ पीपीपी मॉडल पर खोले जाएंगे। इसके लिए कानून में बदलाव किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए कमीशन गठन करने की बात 2019 में की गई थी। इस साल इसे कानून बनाकर अमल में लाया जाएगा। पढ़िए सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण ऐलान...

750 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए 38 करोड़ रुपए

आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य आदर्श रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे। इसके लिए बजट 20 करोड़ रु. से बढ़ाकर 38 करोड़ रु. किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों के लिए स्कूलों को 48 करोड़ दिए गए हैं। एससी छात्रों की पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अगले 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

क्यों- देश के करीब 4 करोड़ एससी छात्रों को 10वीं के बाद शिक्षा जारी रखने में मदद मिल सकेगी।

5 साल में 48% बढ़ा था शिक्षा बजट

(राशि करोड़ रुपए में)



लद्दाख में उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी शुरू की जाएगी। पीएम मोदी ने इसके लिए 2020 में मंजूरी दी थी।

क्यों- 10 हजार छात्रों को हर साल पढ़ाई के लिए घर छोड़ना पड़ता है। उन्हें राज्य में ही बेहतर शिक्षा मिलेगी।

कौशल विकास: जापान-यूई का साथ

देश के वर्कफोर्स को वैश्विक स्तर पर स्किलड बनाने के लिए जापान के साथ इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम की जानकारी दी गई है। इसे कई देशों के साथ भी शुरू किया जाएगा। यूई के साथ ऐसी एक ट्रेनिंग पार्टनरशिप पर काम चल रहा है।

क्यों- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल आधारित पढ़ाई पर फोकस है। इसलिए ये प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं।

अप्रेंटिसशिप एक्ट में बदलाव: पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन व डिप्लोमा करने वालों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी।